सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 296
04–03–2010

2004–05 से 2008–09 के बीच अर्थ व्यवस्था 11.35 की वार्षिक दर से बढ़ी है

––– प्रधान सचिव, वित्त विभाग

पटना 04 मार्च :: प्रधान सचिव, वित्त विभाग श्री भानु प्रताप शर्मा ने बताया कि आज बिहार विधान मंडल में 2009–10 का 'आर्थिक सर्वेक्षण' प्रस्तुत किया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि इसमें राज्य की अर्थ व्यवस्था का विश्लेषण उपलब्ध है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2009–10 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल में आए परिवर्तनों के संबंध में अनेक पर्यवेक्षणों की पुष्टि होती है। वर्ष 2008–09 में 1999–00 के मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 98,392.6 करोड़ रू0 था जिससे प्रति व्यक्ति आय 10,415 रू0 थी। वर्ष 1999–00 से पहले पांच वर्षो के दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था में 3.50 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। उसके बाद 2004–05 से 2008–09 के बीच अर्थव्यवस्था 11.35 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। उच्च वृद्धि दर वाले तीन प्रक्षेत्र हैं– निर्माण (35.80 प्रतिशत), संचार (17.68 प्रतिशत) तथा व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट (17.71 प्रतिशत)।

श्री शर्मा ने कहा कि कृषि मजदूर हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से पता चलता है कि बिहार में मूल्यवृद्धि राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम रही है। वर्ष 2007–08 से नवंबर 2009–10 के बीच सूचकांक बिहार में 90 अंक बढ़ा जबकि संपूर्ण भारत के सूचकांक में 115 अंकों की वृद्धि हुई। बिहार में रोजगार के सबसे बड़े स्त्रोत कृषि में एक वर्ष में फसल सघनता .1.33 से बढ़कर 1.36 हो गई। 2006–07 में कृषिगत क्षेत्रफल में 322 हजारहेक्टेयर भूमि अतिरिक्त जुड़ी थी। वर्ष 2003–04 से 2008–09 तक कृषि ऋण प्रवाह में 265 प्रतिशत वृद्धि हुई।

प्रधान सचिव वित्त ने बताया कि सभी श्रेणियों के उद्योगों की संख्या 51.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2004–05 से कारीगरी आधारित इकाइयों में 57.8प्रतिशत, अतिलघु/सूक्ष्म इकाइयों में 47.4 प्रतिशत और लघु उद्योग इकाइयों में 21.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। निवेश में 147 प्रतिशत की वृद्धि हुई और रोजगार में 33.9

प्रतिशत की। नवंबर 2009 तक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा कुल 133.84 हजार करोड़ रू0 के निजी निवेश तथा 1.38 लाख रोजगार की क्षमता वाले 245 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

विदेशी पर्यटकों के आगमन में लगभग छःगुनी वृद्धि दिखी है जो 2003 के लगभग 61 हजार से बढ़कर 2008 में 3.46 लाख हो गई है। इसी प्रकार घरेलू पर्यटन में दोगुनी से भी अधिक वृद्धि दर्ज हुई है और पर्यटकों की संख्या 2003 के 52.28 लाख से बढ़कर 2008 में 118.90 लाख हो गई है।

प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों के महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए है। सड़कों पर व्यय 2005–06 के 263.23 करोड़ रु0 की तुलना में दसगुना बढ़ाकर 2008–09 में 2,489.15 करोड़ रू0 हो गया है। वर्ष 2005–06 के 415 कि0मी0 की तुलना में राज्य सरकार ने 2008–09 में 2,417 कि0मी0 सडकों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पूरक के बतौर राज्य सरकार 500 या अधिक जनसंख्या वाली बसाटों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क संपर्क उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2006–07 से 2009–10 के बीच इन दोनों योजनाओं की उपलब्धियां इस प्रकार हैं– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 323 कि0मी0 तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 1,91कि0मी0। राज्य में गुणवत्तापूर्ण पुलों के निर्माण के लिए 2006 में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना आरंभ की गई थी। अभी तक जिन 520 पुलों के निर्माण की योजना बनी थी, 712.33 करोड़ रू0 के व्यय से उनमें से 375 पुल बनाए जा चुके है। इनके अलावा, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत 492.26करोड़ रू0 के व्यय से 1,104 छोटे पुल भी बनाए गए हैं । बिहार में परिवहन प्रक्षेत्र का काफी तेज गति से विस्तार हुआ है। वर्ष 2005–06 में जहां 80.4 हजार वाहनों का पंजीकरण हुआ था, वहीं 50.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2008–09 में इनकी संख्या 220.4 हजार हो गई। दूर संचार प्रक्षेत्र का भी असाधारण विकास हो रहा है। मार्च 2006 से अक्टूबर 2009

के बीच टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या 42.23 लाख से छः गुनी बढ़कर 265.21 लाख हो गई है।

श्री शर्मा ने बताया कि वर्ष 2002–03 से 2007–08 तक प्राथमिक स्तर पर समग्र नामांकन में 58.5 प्रशित वृद्धि हुई। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह वृद्धि 159.4 प्रतिशत थी । उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जातियों का नामांकन 187.4 प्रतिशत बढ़ा और अनुसूचित जनजातियों का 424.2 प्रतिशत। प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लिए ये आंकड़े क्रमशः 66.3 प्रतिशत और 270.0 प्रतिशत हैं। गत कुछ वर्षो में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनों स्तरों पर लड़कियों का नामांकन प्रतिशत काफी ऊंचा रहा है। बिहार में 2001–02 से 2006–07 के बीच प्राथमिक शिक्षा में छीजन दर में 15.5 प्रतिशत कमी आई है। लड़कियों के मामले में यह कमी और भी अधिक है। महाविद्यालयों की कुल संख्या 2004 में 743 थी जो 2007 में बढ़कर 815 हो गई । स्वास्थ्य अधिसंरचना में 2001 से 2006 के बीच आई चिरकालिक गिरावट 2007 से पलट गई है। अक्टूबर 2009 में राज्य में 10,634 स्वास्थ्य केन्द्र थे। वर्ष 2005–06 से प्रसवपूर्व तथा प्रसव–पश्चात देखरेख के परिणाम संबंधी सूचकों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। शिशु मृत्यु दर 2005 में 61 थी जो 2009 में 56 रह गई है। मातृ मृत्यु दर 2001–03 में 371 थी जो 2004–06 में 312 रह गई । कुल प्रजनन दर 2005–06 में 4.3 थी जो 2009 में 3.9 रह गई है। प्रतिरक्षण दर 2002–04 के 20.7 प्रतिशत से बढत्रकर 2007–08 में 41.4 हो गई है।

प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने 2008–09 से जेंडर बजट तैयार करना आरंभ किया है। न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला लाभार्थियों वाली योजनाओं में परिव्यय बढ़ने से 2008′09 और 2009–10 के बीच के एकमात्र वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के बतौर जेंडर बजट का आकार दूना हो गया है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना लैंगिक असमानता कम करने हेतु राज्य सरकार के हस्तक्षेप हैं।

प्रधान सचिव (वित्त) ने बताया कि मार्च 2009 में बिहार में स्थित व्यावसायिक बैंकों की कुल 3,916 शाखाओं में से 60.2 प्रतिशत ग्रामीण, 21.6 प्रतिशत अर्धशहरी तथा 18.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में अवस्थित थी। वर्ष 2008–09 में बैंक शाखाओं में 3.27 प्रतिशत वृद्धि हुई। मार्च 2009 में देश के व्यावसायिक बैंकों में कुल जमा में बिहार का हिस्सा 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गया । बहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुल जमा 2005–06 के 6,199 करोड़ रू0 से बढ़कर 2008–09 में 11,079 करोाड़ रू0 हो गया है। बिहार में वर्त्तमान ऋण–जमा अनुपात लगभग 31 प्रतिशत है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार का राजस्व अधिशेष 2004–05 के 1,076 करोड़ रू0 से लगभग चारगुना बढ़सकर 2008–09 में 4,469 करोड़ रू0 हो गया। यह अधिशेष 2005–06 से 2008–09 तक लगातार बढ़ा और यह रूझान 2009–10 में जारी रहेगा। इससे राज्य सरकार का पूंजीगत परिव्यय लगभग तीनगुना बढ़ा– 2005–06 के 2,084 करोड़ रू0 से 2008–09 में 6,436 करोड़ रू0। वर्ष 2009–10 में पूंजीगत परिव्यय लगभग 50 प्रतिशत बढ़कर 9,505 करोड रू0 हो गया है।

प्रधान सचिव ने दावा किया कि कुशल ऋण प्रबंधन के कारण कुल ऋण संचय के साथ–साथ ब्याज भुगतानों में भी कमी आई है। अभी ये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लगभग 30 प्रतिशत और 3 प्रतिशत हैं जो पांच वर्ष पूर्व क्रमशः 40 प्रतिशत और 5 प्रतिशत थे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर बकाया देनदारी 2004–05 के 43.1 प्रतिशत से घटकर 2009–10 में 29.2 प्रतिशत रह गई है। राज्य सरकार का कुल राजस्व लगभग 28 प्रतिश की वार्षिक दर से बढ़कर 2004–05 के 15,714 करोड़ रू0 से 2009–10 में 37,870 करोड़ रु0 हो गया है । वर्ष 2004–05 से 2009–10 के बीच कुल व्यय में विकास व्यय का हिस्सा

40 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गया है। निरपेक्ष रूप से देखें तो राशि में चारगुनी वृद्धि हुई है। वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक शिक्षा व्यय का बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा के लिए समर्पित था।

————————————